The ACHIEVERS IAS ACADEMY

The ACHIEVERS
IAS ACADEMY
PATNA

Daily NEWS CHRONICLE

IDEAL FOR
For UPSC/BPSC & For other Exams

Hindi

NEWS CREDIT
PIB/ PTI/ News On Air/ The Hindu/ IANS/ Business Standard/ Times Of India/ Deccan Herald/ Hindustan Times/ BBC News/ Aljazeera/ Mirror.Uk/ Times Now/ Economic Times/ Financial Express/ Indian Express...

NEWS COVERED
Business News, financial news, economy news, company news, politics news, India news, breaking news, Indian economy, International News, Sports News, and many more topics...

Thursday, July 09, 2026

+91 8434931877 www.achieversiaspatna.co.in achieversiaspatna@gmail.com

दिन की प्रमुख घटनाएं

- NPCI के CEO दिलीप अस्बे SWIFT पर्यवेक्षी बोर्ड में शामिल हुए, वैश्विक डिजिटल भुगतान में भारत की भूमिका को मजबूत करते हैं
- दक्षिण कोरिया, अमेरिका और जापान ने छोटे मॉड्यूलर रिएक्टरों की वैश्विक तैनाती के लिए त्रिपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किए
- केंद्र ने पुलिस प्रशासन को मजबूत करने के लिए बीपीआरएंडडी, एनसीआरबी और एसवीपीएनपीए के लिए नए प्रमुखों की नियुक्ति की
- पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित गिरीश भारद्वाज का 76 साल की उम्र में निधन
- भारत और रवांडा ने दूसरी संयुक्त रक्षा सहयोग समिति की बैठक के दौरान रक्षा सहयोग का विस्तार किया
- आईओसी ने रूसी ओलंपिक समिति का निलंबन हटाया, लॉस एंजिलिस 2028 में भाग लेने का रास्ता खोला
- भारत ने आसियान-भारत व्यापार समझौते के आधुनिकीकरण के लिए 13वीं एआईटीआईजीए संयुक्त समिति की बैठक की मेजबानी की
- नेपाल के जेष्ठ वर्ण महाविहार को भारत समर्थित बहाली के बाद यूनेस्को विरासत संरक्षण पुरस्कार मिला
- स्वीडन वैश्विक पासपोर्ट सूचकांक 2026 में सबसे ऊपर है जबकि भारत वैश्विक गतिशीलता रैंकिंग में 125वें स्थान पर है
- ब्रिक्स ने अवैध मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ वैश्विक लड़ाई को मजबूत करने के लिए गुवाहाटी घोषणा को अपनाया
- दिल्ली सरकार ने सरकारी स्कूलों को आधुनिक बुनियादी ढांचे से बदलने के लिए मिशन कायाकल्प शुरू किया

एनपीसीआई के एमडी और सीईओ दिलीप अस्बे स्विफ्ट के वैश्विक पर्यवेक्षी बोर्ड में शामिल हुए

यह खबरों में क्यों है?

- नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) के प्रबंध निदेशक और CEO दिलीप अस्बे को SWIFT (सोसाइटी फॉर वर्ल्डवाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन) के पर्यवेक्षी बोर्ड में नियुक्त किया गया है। यह नियुक्ति वैश्विक डिजिटल भुगतान पारिस्थितिकी तंत्र में भारत के बढ़ते प्रभाव को दर्शाती है।

मुख्य बिंदु

- एनपीसीआई के एमडी और सीईओ दिलीप अस्बे स्विफ्ट पर्यवेक्षी बोर्ड में शामिल हो गए हैं।
- उनकी नियुक्ति वैश्विक वित्तीय शासन और अंतर्राष्ट्रीय भुगतान प्रणालियों में भारत के प्रतिनिधित्व को मजबूत करती है।
- SWIFT अंतरराष्ट्रीय वित्तीय लेनदेन के लिए सुरक्षित संचार को सुविधाजनक बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
- डिजिटल भुगतान में भारत की बढ़ती सफलता, विशेष रूप से यूपीआई के माध्यम से, ने वैश्विक भुगतान बुनियादी ढांचे को आकार देने में इसकी बढ़ती भूमिका में योगदान दिया है।
- इस नियुक्ति से सीमा पार भुगतान और वित्तीय प्रौद्योगिकी के क्षेत्रों में भारत और वैश्विक वित्तीय संस्थानों के बीच सहयोग बढ़ने की उम्मीद है।

स्विफ्ट क्या है?

- स्विफ्ट (सोसाइटी फॉर वर्ल्डवाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन) एक वैश्विक वित्तीय संदेश नेटवर्क है जो बैंकों और वित्तीय संस्थानों को भुगतान निर्देशों और अन्य वित्तीय संदेशों का सुरक्षित रूप से आदान-प्रदान करने में सक्षम बनाता है।
- यह पैसे ट्रांसफर नहीं करता है। इसके बजाय, यह एक सुरक्षित, मानकीकृत संदेश प्रणाली प्रदान करता है जो बैंकों को भुगतान निर्देशों को सटीक और कुशलता से संप्रेषित करने की अनुमति देता है।

स्विफ्ट कैसे काम करता है?

- जब कोई ग्राहक अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पैसा भेजता है, तो प्रेषक का बैंक प्राप्तकर्ता के बैंक को एक सुरक्षित भुगतान संदेश भेजने के लिए स्विफ्ट नेटवर्क का उपयोग करता है।
- इस संदेश के आधार पर, प्राप्तकर्ता बैंक संसाधित करता है और लाभार्थी के खाते में धनराशि जमा करता है।
- इस प्रकार, स्विफ्ट एक संचार नेटवर्क के रूप में कार्य करता है, जबकि धन की वास्तविक आवाजाही संवाददाता बैंकिंग व्यवस्था के माध्यम से होती है।

स्विफ्ट की मुख्य विशेषताएं

- वित्तीय संस्थानों के लिए एक सुरक्षित और एन्क्रिप्टेड मैसेजिंग प्लेटफॉर्म प्रदान करता है।
- 200+ देशों और क्षेत्रों में 11,000 से अधिक वित्तीय संस्थानों को जोड़ता है।
- बैंकों की पहचान करने के लिए विश्व स्तर पर स्वीकृत स्विफ्ट/बीआईसी (बैंक पहचानकर्ता कोड) का उपयोग करता है।
- हर दिन लाखों वित्तीय संदेशों को संभालता है।
- अंतरराष्ट्रीय भुगतान, विदेशी मुद्रा लेनदेन, प्रतिभूति व्यापार और व्यापार वित्त का समर्थन करता है।
- इसे वैश्विक सीमा पार बैंकिंग संचार की रीढ़ माना जाता है।

स्विफ्ट के कार्य

• अंतर्राष्ट्रीय फंड ट्रांसफर निर्देशों की सुविधा प्रदान करता है।
• व्यापार वित्त और साख पत्रों के लिए संचार को सक्षम बनाता है।
• प्रतिभूति निपटान और ट्रेजरी संचालन का समर्थन करता है।
• देशों में वित्तीय संदेश को मानकीकृत करता है।
• वैश्विक बैंकिंग में गति, सुरक्षा और सटीकता में सुधार करता है।

स्विफ्ट और भारत

- भारतीय बैंक अंतरराष्ट्रीय प्रेषण और सीमा पार व्यापार लेनदेन के लिए स्विफ्ट नेटवर्क का उपयोग करते हैं।
- भारत के डिजिटल भुगतान नवाचार, जैसे यूपीआई, को तेजी से वैश्विक भुगतान इकोसिस्टम के साथ एकीकृत किया जा रहा है।
- स्विफ्ट के पर्यवेक्षी बोर्ड में एनपीसीआई प्रमुख की नियुक्ति अंतरराष्ट्रीय भुगतान प्रणालियों के आधुनिकीकरण में भारत की बढ़ती भूमिका को उजागर करती है।

महत्व

- वैश्विक वित्तीय शासन में भारत की आवाज को बढ़ाता है।

- अंतर्राष् ट्रीय भुगतान अवसंरचना में भारत की स् थान को मजबूत करता है।
- सीमा पार डिजिटल भुगतान में सहयोग को बढ़ावा देता है।
- भारत के फिनटेक इकोसिस्टम के वैश्विक विस्तार का समर्थन करता है।
- यह डिजिटल भुगतान नवाचार में भारत के नेतृत्व की अंतर्राष्ट्रीय मान्यता को दर्शाता है।

परीक्षा फोकस पॉइंट

• नियुक्त व्यक्ति: दिलीप अस्बे
• पद: एमडी और सीईओ, नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (एनपीसीआई)
• संगठन: स्विफ्ट (सोसाइटी फॉर वर्ल्डवाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन)
• पद: सदस्य, स्विफ्ट पर्यवेक्षी बोर्ड
• स्विफ्ट की स्थापना: 1973
• मुख्यालय: ला हुल्पे, बेल्जियम
• प्रकृति: वैश्विक वित्तीय संदेश नेटवर्क
• प्राथमिक कार्य: बैंकों के बीच वित्तीय संदेशों का सुरक्षित आदान-प्रदान
• स्विफ्ट कोड: बैंक पहचानकर्ता कोड (बीआईसी)
• मनी ट्रांसफर: SWIFT पैसे ट्रांसफर नहीं करता है; यह भुगतान निर्देशों को सुरक्षित रूप से प्रसारित करता है।
• भारतीय डिजिटल भुगतान ऑपरेटर: भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (एनपीसीआई)
• NPCI की प्रमुख भुगतान प्रणाली: यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI)

दक्षिण कोरिया, संयुक्त राज्य अमेरिका और जापान छोटे मॉड्यूलर रिएक्टर (एसएमआर) की तैनाती पर सहयोग करने पर सहमत हुए

- कोरिया गणराज्य (दक्षिण कोरिया), संयुक्त राज्य अमेरिका और जापान ने तीसरे देशों में छोटे मॉड्यूलर रिएक्टरों (एसएमआर) की तैनाती को संयुक्त रूप से बढ़ावा देने के लिए एक त्रिपक्षीय सहयोग ज्ञापन (एमओसी) पर हस्ताक्षर किए।

त्रिपक्षीय समझौते की मुख्य विशेषताएं:

- भाग लेने वाले देश: दक्षिण कोरिया, संयुक्त राज्य अमेरिका और जापान।
- समझौता: SMR परिनियोजन पर त्रिपक्षीय सहयोग ज्ञापन (MoC)।

द्वारा हस्ताक्षरित:

• चो ह्यून – दक्षिण कोरिया के विदेश मंत्री।
• मार्को रुबियो – अमेरिकी विदेश मंत्री।
• तोशिमित्सु मोतेगी - जापान के विदेश मंत्री
• फोकस: भागीदार देशों में एसएमआर की संयुक्त तैनाती।
• उद्देश्य: सुरक्षित, किफायती और विश्वसनीय स्वच्छ ऊर्जा समाधान प्रदान करना।
• स्थान: नाटो शिखर सम्मेलन के मौके पर हस्ताक्षरित।

छोटे मॉड्यूलर रिएक्टर (एसएमआर) क्या हैं?

- छोटे मॉड्यूलर रिएक्टर (एसएमआर) उन्नत परमाणु विखंडन रिएक्टर हैं जिनकी बिजली उत्पादन क्षमता 300 मेगावाट (ई) प्रति यूनिट तक है - पारंपरिक परमाणु रिएक्टरों के उत्पादन का लगभग एक-तिहाई। वे फ़ैक्टरी-निर्मित, डिज़ाइन में मॉड्यूलर हैं, और स्थापना के लिए परियोजना स्थलों पर ले जाया जा सकता है।

एसएमआर के क्या फायदे हैं?

- पारंपरिक परमाणु संयंत्रों की तुलना में छोटे पदचिह्न।
- कम प्रारंभिक पूंजी निवेश।
- मॉड्यूलर निर्माण परियोजना के पूरा होने के समय को कम करता है।
- बढ़ी हुई निष्क्रिय सुरक्षा प्रणाली।
- दूरदराज के क्षेत्रों और छोटे बिजली ग्रिड के लिए उपयुक्त।
- हाइड्रोजन उत्पादन, अलवणीकरण और औद्योगिक ताप अनुप्रयोगों का समर्थन कर सकता है।
- जीवाश्म-ईंधन-आधारित बिजली उत्पादन की तुलना में कम ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन।

एसएमआर से जुड़ी चुनौतियाँ:

- उच्च प्रारंभिक प्रौद्योगिकी विकास लागत।
- लाइसेंसिंग और नियामक अनुमोदन चुनौतियाँ।

- रेडियोधर्मी कचरे का प्रबंधन और निपटान।
- परमाणु सुरक्षा के बारे में सार्वजनिक चिंताएं।
- मजबूत परमाणु सुरक्षा और सुरक्षा उपायों की आवश्यकता।

परमाणु ऊर्जा के बारे में:

- ऊर्जा स्रोत: परमाणु विखंडन के माध्यम से उत्पादित, मुख्य रूप से यूरेनियम -235 या प्लूटोनियम -239 का उपयोग करके।
- प्रकृति: बिजली का कम कार्बन स्रोत।
- वैश्विक महत्व: जलवायु परिवर्तन शमन और ऊर्जा सुरक्षा लक्ष्यों को प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

भारत में परमाणु ऊर्जा:

- विभाग: परमाणु ऊर्जा विभाग (डीएई)।
- नियामक प्राधिकरण: परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड (एईआरबी)।
- प्रमुख ऑपरेटर: न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (एनपीसीआईएल)।
- भारत का त्रि-चरणीय परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम: डॉ. होमी जहांगीर भाभा द्वारा प्रस्तावित।
- प्राकृतिक यूरेनियम का उपयोग करते हुए दाबित भारी पानी रिएक्टरों (पीएचडब्ल्यूआर)।
- फास्ट ब्रीडर रिएक्टर (एफबीआर) प्लूटोनियम का उपयोग करते हुए।
- यूरेनियम-233 (भारत में दुनिया के सबसे बड़े थोरियम भंडारों में से एक है) का उपयोग करने वाले थोरियम आधारित रिएक्टर।

अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी (IAEA) के बारे में:

- स्थापित: 1957.
- मुख्यालय: वियना, ऑस्ट्रिया।
- प्रकार: संयुक्त राष्ट्र प्रणाली के तहत स्वायत्त अंतर्राष्ट्रीय संगठन।
- उद्देश्य: परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग को बढ़ावा देना और इसके सैन्य उपयोग को रोकना।
- सामान्य निदेशक: राफेल मारियानो ग्रॉसी।

परीक्षा फोकस बिंदु:

- समझौता: छोटे मॉड्यूलर रिएक्टरों (एसएमआर) पर त्रिपक्षीय सहयोग ज्ञापन।
- देश: दक्षिण कोरिया, संयुक्त राज्य अमेरिका और जापान।
- उद्देश्य: तीसरे देशों में एसएमआर की संयुक्त तैनाती।
- प्रौद्योगिकी: छोटे मॉड्यूलर रिएक्टर (एसएमआर)।
- एसएमआर की अधिकतम क्षमता: प्रति यूनिट 300 मेगावाट (ई) तक।
- अंतर्राष्ट्रीय परमाणु एजेंसी: अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी (आईएईए)।
- IAEA मुख्यालय: वियना, ऑस्ट्रिया।
- भारत का परमाणु ऊर्जा ऑपरेटर: न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (एनपीसीआईएल)।
- भारत के परमाणु कार्यक्रम वास्तुकार: डॉ. होमी जहांगीर भाभा।
- महत्व: स्वच्छ ऊर्जा, ऊर्जा सुरक्षा और डीकार्बोनाइजेशन।

केंद्र ने बीपीआरएंडडी, एनसीआरबी और एसवीपीएनपीए के लिए नए प्रमुखों की नियुक्ति की

- कैबिनेट की नियुक्ति समिति (ACC) ने गृह मंत्रालय (MHA) के तहत तीन प्रमुख पुलिस संस्थानों- पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो (BPR&D), राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) और सरदार वल्लभभाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी (SVPNPA) के लिए नए प्रमुखों की नियुक्ति को मंजूरी दे दी है।

प्रमुख नियुक्तियां:

- आलोक कुमार मित्तल (आईपीएस, 1993 बैच, हरियाणा कैडर) को पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो (बीपीआर एंड डी) के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है।
- अमित गर्ग (आईपीएस, 1993 बैच, आंध्र प्रदेश कैडर) को राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। इस पद को उनकी सेवानिवृत्ति तक अस्थायी रूप से महानिदेशक (डीजी) स्तर पर अपग्रेड किया गया है।
- सुजीत पांडे (आईपीएस, 1994 बैच, उत्तर प्रदेश कैडर) को सरदार वल्लभभाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी (एसवीपीएनपीए) के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है।

पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो (BPR&D) के बारे में

- बीपीआरएंडडी भारत में पुलिस सुधारों, अनुसंधान और आधुनिकीकरण के लिए जिम्मेदार प्रमुख संस्थान है।
- स्थापना: 28 अगस्त 1970।
- प्रशासनिक मंत्रालय: गृह मंत्रालय (एमएचए)।
- मुख्यालय: नई दिल्ली।

कार्य:

- पुलिस अनुसंधान और नीति निर्माण।
- पुलिसिंग आधुनिकीकरण।
- पुलिसिंग प्रौद्योगिकियों का विकास।
- प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण।
- सुधारात्मक प्रशासन और जेल सुधार।
- मॉडल पुलिस मैनुअल और सर्वोत्तम प्रथाओं का विकास।

राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) के बारे में

- एनसीआरबी अपराध डेटा संग्रह, विश्लेषण और आपराधिक सूचना प्रबंधन के लिए भारत की केंद्रीय एजेंसी है।

महत्वपूर्ण तथ्य

- स्थापित: 1986।
- प्रशासनिक मंत्रालय: गृह मंत्रालय।
- मुख्यालय: नई दिल्ली।

प्रमुख प्रकाशन:

- भारत में अपराध रिपोर्ट (वार्षिक रूप से प्रकाशित)।
- भारत में आकस्मिक मौतें और आत्महत्याएं (एडीएसआई)।
- जेल सांख्यिकी भारत।

प्रमुख परियोजनाएं:

- अपराध और आपराधिक ट्रैकिंग नेटवर्क और सिस्टम (सीसीटीएनएस)।
- राष्ट्रीय स्वचालित फिंगरप्रिंट पहचान प्रणाली (एनएएफआईएस)।
- इंटर-ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम (आईसीजेएस)।
- यौन अपराधियों पर राष्ट्रीय डेटाबेस (एनडीएसओ)।

सरदार वल्लभभाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी (SVPNPA) के बारे में:

- एसवीपीएनपीए भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) अधिकारियों के लिए भारत का प्रमुख प्रशिक्षण संस्थान है।

महत्वपूर्ण तथ्य

- स्थान: हैदराबाद, तेलंगाना।
- प्रशासनिक मंत्रालय: गृह मंत्रालय।

भूमिका:

- आईपीएस परिवीक्षाधीनों का बुनियादी प्रशिक्षण।
- मध्य कैरियर प्रशिक्षण कार्यक्रम।
- नेतृत्व विकास।
- आतंकवाद विरोधी और साइबर अपराध प्रशिक्षण।
- आंतरिक सुरक्षा और जांच पाठ्यक्रम।

कैबिनेट की नियुक्ति समिति (ACC) के बारे में:

- अध्यक्ष: भारत के प्रधान मंत्री।
- सदस्य: केंद्रीय गृह मंत्री।
- कार्य: भारत सरकार में सचिवों, महानिदेशकों और स्वायत्त निकायों के प्रमुखों सहित शीर्ष पदों पर वरिष्ठ अधिकारियों की नियुक्ति करता है।

परीक्षा फोकस बिंदु:

- द्वारा अनुमोदित नियुक्तियाँ: कैबिनेट की नियुक्ति समिति (एसीसी)।
- प्रशासनिक मंत्रालय: गृह मंत्रालय (एमएचए)।
- बीपीआरएंडडी के महानिदेशक : आलोक कुमार मित्तल।
- निदेशक, एनसीआरबी: अमित गर्ग।
- डायरेक्टर, एसवीपीएनपीए : सुजीत पांडेय
- बीपीआर एंड डी की स्थापना: 1970।
- एनसीआरबी की स्थापना: 1986।
- एसवीपीएनपीए स्थान: हैदराबाद, तेलंगाना।
- एनसीआरबी की प्रमुख परियोजनाएं: सीसीटीएनएस, आईसीजेएस, एनएएफआईएस, एनडीएसओ।
- प्रीमियर आईपीएस प्रशिक्षण अकादमी: सरदार वल्लभभाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी।

'ब्रिज मैन ऑफ इंडिया' गिरीश भारद्वाज का 76 साल की उम्र में निधन

- पद्म श्री पुरस्कार विजेता गिरीश भारद्वाज, जिन्हें "भारत के ब्रिज मैन" के रूप में जाना जाता है, का 76 वर्ष की आयु में कर्नाटक के सुलिया में एक संक्षिप्त बीमारी के बाद निधन हो गया।

प्रमुख योगदान:

- पूरे भारत में 140 से अधिक कम लागत वाले सस्पेंशन फुटब्रिज का डिजाइन और निर्माण किया गया।
- पहला सस्पेंशन ब्रिज: 1989 में निर्मित।
- दूरदराज और जनजातीय क्षेत्रों में कनेक्टिविटी में सुधार के लिए 35 वर्षों से अधिक समय समर्पित किया गया।
- उनके पुल के डिजाइन किफायती, टिकाऊ थे और न्यूनतम रखरखाव की आवश्यकता थी।

प्रमुख मान्यता

- पद्म श्री: 2017।
- ग्रामीण बुनियादी ढांचे के विकास और सोशल इंजीनियरिंग में नवाचार के लिए राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त है।
- व्यापक रूप से भारत के अग्रणी जमीनी स्तर के नवप्रवर्तकों में से एक के रूप में स्वीकार किया जाता है।

पद्म पुरस्कारों के बारे में

- पद्म पुरस्कार भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में से हैं और भारत के राष्ट्रपति द्वारा प्रदान किए जाते हैं।

श्रेणियाँ (वरीयता के क्रम में)

- भारत रत्न
- पद्म विभूषण
- पद्म भूषण
- पद्म श्री

महत्वपूर्ण तथ्य

- घोषणा: हर साल गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर।
- द्वारा सम्मानित: भारत के राष्ट्रपति।
- प्रशासनिक मंत्रालय: गृह मंत्रालय (एमएचए)।

इस तरह के क्षेत्रों में असाधारण उपलब्धियों को पहचानें:

- कला
- साहित्य और शिक्षा
- विज्ञान और इंजीनियरिंग
- सार्वजनिक मामले
- दवाई
- सामाजिक कार्य
- सिविल सेवा
- खेल
- व्यापार और उद्योग

सस्पेंशन फुटब्रिज का महत्व

सस्पेंशन फुटब्रिज विशेष रूप से उपयोगी हैं:

- पहाड़ी और पहाड़ी क्षेत्र।
- बाढ़ प्रवण नदी बेसिन।
- आदिवासी और दूरदराज के गांव।
- ऐसे क्षेत्र जहां पारंपरिक पुल निर्माण महंगा या तकनीकी रूप से कठिन है।

लाभ

- प्रभावी लागत।
- तेजी से निर्माण।
- न्यूनतम पर्यावरणीय प्रभाव।
- कठिन इलाके के लिए उपयुक्त।
- ग्रामीण कनेक्टिविटी और आपदा लचीलापन बढ़ाता है।

ग्रामीण कनेक्टिविटी के लिए सरकार की पहल:

- प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई): पात्र ग्रामीण बस्तियों को बारहमासी सड़क संपर्क प्रदान करने के लिए वर्ष 2000 में शुरू की गई थी।
- पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान: मल्टीमॉडल कनेक्टिविटी के लिए एकीकृत बुनियादी ढांचा योजना।
- राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन (एनआईपी): कनेक्टिविटी और लॉजिस्टिक्स में सुधार के लिए दीर्घकालिक बुनियादी ढांचा निवेश कार्यक्रम।

परीक्षा फोकस बिंदु:

- व्यक्तित्व (मृत्युलेख): गिरीश भारद्वाज।
- लोकप्रिय शीर्षक: ब्रिज मैन ऑफ इंडिया।
- राज्य: कर्नाटक।
- योगदान: 140 से अधिक कम लागत वाले सस्पेंशन फुटब्रिज का निर्माण किया गया।
- पहला पुल निर्मित: 1989।
- पद्म श्री पुरस्कार: 2017
- क्षेत्र: ग्रामीण बुनियादी ढांचा और सोशल इंजीनियरिंग।
- के लिए जाना जाता है: दूरदराज के गांवों के लिए सस्पेंशन ब्रिज तकनीक।
- रिलेटेड स्कीम: प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई)।

भारत और रवांडा जेडीसीसी की दूसरी बैठक में द्विपक्षीय रक्षा साझेदारी का विस्तार करने पर सहमत हुए

- भारत और रवांडा नई दिल्ली में आयोजित दूसरी संयुक्त रक्षा सहयोग समिति (JDCC) की बैठक के दौरान अपने द्विपक्षीय रक्षा सहयोग को गहरा करने पर सहमत हुए।
- दोनों देशों ने सैन्य प्रशिक्षण, संयुक्त सैन्य अभ्यास, रक्षा उद्योग और सैन्य चिकित्सा सहयोग में सहयोग का विस्तार करने का निर्णय लिया।
- उन्होंने सहमत कार्य बिंदुओं के लिए समयसीमा के साथ एक कार्यान्वयन योजना को भी मंजूरी दी, जो दीर्घकालिक रक्षा संबंधों को मजबूत करने की उनकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
- बैठक की सह-अध्यक्षता भारत के रक्षा मंत्रालय के संयुक्त सचिव अमिताभ प्रसाद और रवांडा रक्षा बल मुख्यालय के संयुक्त बल विकास, प्रशिक्षण और सिद्धांत के प्रमुख ब्रिगेडियर जनरल लुई कानोबायर (चीफ जे 7) ने की।

अतिरिक्त विकास:

- रवांडा के प्रतिनिधिमंडल ने रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह से मुलाकात की।
- प्रतिनिधिमंडल ने भारतीय रक्षा उद्योग के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत की और स्वदेशी रक्षा निर्माण में अवसरों का पता लगाया।
- प्रतिनिधिमंडल ने भारत के सैन्य स्वास्थ्य देखभाल बुनियादी ढांचे और चिकित्सा सहायता प्रणालियों का अध्ययन करने के लिए नई दिल्ली के सेना अस्पताल (रेफरल एंड रिसर्च) का दौरा किया।
- दोनों देश रक्षा उत्पादन और प्रौद्योगिकी में सहयोग में तेजी लाने पर सहमत हुए।

संयुक्त रक्षा सहयोग समिति (JDCC) के बारे में:

- संयुक्त रक्षा सहयोग समिति (JDCC) भागीदार देशों के बीच रक्षा सहयोग की समीक्षा और उसे मजबूत करने के लिए स्थापित एक द्विपक्षीय संस्थागत तंत्र है।

कार्य

- रक्षा सहयोग में प्रगति की समीक्षा करें।
- सैन्य सहयोग के नए क्षेत्रों की पहचान करें।
- रक्षा औद्योगिक साझेदारी को बढ़ावा देना।
- सैन्य प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण को बढ़ाना।
- द्विपक्षीय रक्षा समझौतों के कार्यान्वयन को सुगम बनाना।

भारत-रवांडा रक्षा संबंध:

- रक्षा सहयोग समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर: जुलाई 2018, प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी की रवांडा यात्रा के दौरान।

सहयोग के क्षेत्रों में शामिल हैं:

- सैन्य प्रशिक्षण।
- रक्षा क्षमता निर्माण।
- रक्षा विनिर्माण।
- शांति स्थापना सहयोग।
- चिकित्सा सहायता।
- विशेषज्ञता और सर्वोत्तम प्रथाओं का आदान-प्रदान।

भारत-रवांडा द्विपक्षीय संबंध:

- राजनयिक संबंधों की स्थापना: 1999।
- किगाली में भारतीय मिशन: 2018 में खोला गया।

सहयोग के प्रमुख क्षेत्र:

- रक्षा और सुरक्षा।
- कृषि।

- स्वास्थ्य देखभाल।
- शिक्षा और क्षमता निर्माण।
- डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचा।
- व्यापार और निवेश।

- भारतीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग (आईटीईसी) कार्यक्रम के तहत विकास भागीदारी।

रवांडा के बारे में:

- आधिकारिक नाम: रवांडा गणराज्य।
- राजधानी: किगाली।
- मुद्रा: रवांडा फ्रैंक (आरडब्ल्यूएफ)।
- राष्ट्रपति: पॉल कागामे।
- क्षेत्र: पूर्वी अफ्रीका।

के सदस्य:

- अफ्रीकी संघ (एयू)।
- पूर्वी अफ्रीकी समुदाय (ईएसी)।
- राष्ट्रों का राष्ट्रमंडल।
- संयुक्त राष्ट्र (यूएन)।

ITEC (भारतीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग) के बारे में:

- लॉन्च किया गया: 1964।
- नोडल मंत्रालय: विदेश मंत्रालय (एमईए)।

उद्देश्य: भागीदार देशों के लिए क्षमता निर्माण और तकनीकी सहायता:

- प्रशिक्षण कार्यक्रम।
- छात्रवृत्ति।
- विशेषज्ञ प्रतिनियुक्ति।
- प्रौद्योगिकी हस्तांतरण।
- संस्थागत विकास।

परीक्षा फोकस बिंदु:

- बैठक: दूसरी संयुक्त रक्षा सहयोग समिति (JDCC)।
- देश: भारत और रवांडा।
- स्थान: नई दिल्ली।
- तिथियाँ: 6-7 जुलाई 2026।
- सह-अध्यक्ष (भारत): अमिताभ प्रसाद।
- सह-अध्यक्ष (रवांडा): ब्रिगेडियर जनरल लुई कानोबायर।
- रक्षा सहयोग समझौता ज्ञापन: जुलाई 2018 में हस्ताक्षरित।
- भारत के रक्षा सचिव: राजेश कुमार सिंह।
- प्रमुख क्षेत्र: सैन्य प्रशिक्षण, रक्षा उद्योग, सैन्य अभ्यास, चिकित्सा सहयोग।
- भारतीय क्षमता निर्माण कार्यक्रम: आईटीईसी।

आईओसी ने रूसी ओलंपिक समिति का निलंबन हटाया, लॉस एंजिलिस 2028 ओलंपिक के लिए रास्ता खोला

यह खबरों में क्यों है?

- अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति (IOC) ने रूसी ओलंपिक समिति (ROC) के निलंबन को अस्थायी रूप से हटा दिया है, जिससे रूसी एथलीटों को अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में लौटने और संभावित रूप से लॉस एंजिल्स 2028 ओलंपिक खेलों (LA28) में प्रतिस्पर्धा करने की अनुमति मिल गई है, जो पात्रता नियमों के अधीन है। हालांकि, आईओसी ने अभी तक यह तय नहीं किया है कि रूस को अपने राष्ट्रीय ध्वज, गान या रंग के तहत प्रतिस्पर्धा करने की अनुमति दी जाएगी या नहीं।

मुख्य बिंदु

- आईओसी ने रूसी ओलंपिक समिति (आरओसी) पर लगाए गए निलंबन को अस्थायी रूप से हटा दिया है।
- इस फैसले से रूसी एथलीटों के लिए 2028 लॉस एंजिल्स ओलंपिक के लिए क्वालीफिकेशन स्पर्धाओं में भाग लेने का रास्ता साफ हो गया है।
- ओलंपिक में भाग लेने के लिए रूस के झंडे, गान और राष्ट्रीय रंग को अभी तक बहाल नहीं किया गया है।
- आईओसी के फैसले के बावजूद कई अंतरराष्ट्रीय खेल महासंघ अपने प्रतिबंध लगाना जारी रख सकते हैं।

पृष्ठभूमि

- रूस को 2016 से ओलंपिक प्रतिबंधों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि राज्य प्रायोजित डोपिंग कार्यक्रम के खुलासे के बाद।
- 2022 में यूक्रेन पर रूस के आक्रमण के बाद, आईओसी ने रूसी और बेलारूसी एथलीटों को अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं से प्रतिबंधित करने की सिफारिश की।
- अक्टूबर 2023 में, IOC ने रूसी ओलंपिक समिति (ROC) को निलंबित कर दिया, जब उसने रूसी कब्जे वाले यूक्रेनी क्षेत्रों लुहान्स्क, डोनेट्स्क, खेरसॉन और ज़ापोरिज़्ज़िया में ओलंपिक परिषदों को मान्यता दी, जिसके बारे में IOC ने कहा कि यह ओलंपिक चार्टर और यूक्रेन की राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की क्षेत्रीय अखंडता का उल्लंघन करता है।

IOC ने निलंबन क्यों हटाया?

- आईओसी ने कहा कि आरओसी में अब कब्जे वाले यूक्रेनी क्षेत्रों के खेल संगठन शामिल नहीं हैं और आश्वासन दिया है कि वह वहां गतिविधियों का संचालन नहीं करेगा। आईओसी ने इस बात पर भी जोर दिया कि एथलीटों को उनकी सरकारों के कार्यों के लिए दंडित नहीं किया जाना चाहिए, जबकि रूस के अनुपालन की निगरानी जारी रखनी चाहिए।

महत्व

- LA28 ओलंपिक में एक बड़े रूसी दल के लिए संभावना खोलता है।
- आईओसी के सिद्धांत को पुष्ट करता है कि सरकारी कार्यों के कारण एथलीटों को स्वचालित रूप से प्रतिबंधों का सामना नहीं करना चाहिए।
- अंतरराष्ट्रीय खेलों में रूसी एथलीटों के क्रमिक पुन: एकीकरण में एक महत्वपूर्ण विकास का प्रतीक है।
- रूस-यूक्रेन संघर्ष और रूस के पिछले डोपिंग उल्लंघनों के कारण यह निर्णय विवादास्पद बना हुआ है।
- IOC खेल भागीदारी, डोपिंग रोधी मानकों और भू-राजनीतिक विचारों के बीच संतुलन की तलाश पर प्रकाश डालता है।

परीक्षा फोकस पॉइंट

• संगठन: अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति (आईओसी)
• निर्णय: रूसी ओलंपिक समिति (आरओसी) के निलंबन को अनंतिम रूप से हटाया गया
• लाभार्थी: रूसी ओलंपिक समिति (आरओसी)
• उद्देश्य: रूसी एथलीटों को अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भाग लेने और LA28 के लिए अर्हता प्राप्त करने की अनुमति दें
• 2028 ओलंपिक के मेजबान: लॉस एंजिल्स, संयुक्त राज्य अमेरिका
• निलंबन लगाया गया: अक्टूबर 2023
• निलंबन का कारण: रूस के कब्जे वाले यूक्रेनी क्षेत्रों में ओलंपिक परिषदों की मान्यता
• IOC मुख्यालय: लुसाने, स्विट्जरलैंड
• वर्तमान आईओसी अध्यक्ष: क्रिस्टी कोवेंट्री

भारत ने आसियान-भारत व्यापार समझौते की समीक्षा के लिए एआईटीआईजीए संयुक्त समिति की बैठक की मेजबानी की

यह खबरों में क्यों है?

- भारत व्यापार समझौते की समीक्षा और आधुनिकीकरण में तेजी लाने के लिए नई दिल्ली में आसियान-भारत वस्तु व्यापार समझौते (एआईटीआईजीए) की 13वीं संयुक्त समिति की बैठक की मेजबानी कर रहा है। बैठक का उद्देश्य समझौते को और अधिक व्यापार के अनुकूल बनाना और भारत और आसियान देशों के बीच व्यापार को बढ़ावा देना है।

मुख्य बिंदु

- भारत 6-10 जुलाई 2026 तक नई दिल्ली में हाइब्रिड प्रारूप में 13वीं एआईटीआईजीए संयुक्त समिति की बैठक और संबंधित बैठकों की मेजबानी कर रहा है।
- बैठक में व्यापार नियमों को सरल बनाने और बाजार पहुंच में सुधार के लिए आसियान-भारत वस्तु व्यापार समझौते (एआईटीआईजीए) की समीक्षा की जा रही है।
- संयुक्त समिति के साथ तीन उप-समितियां बैठक कर रही हैं:
- सीमा शुल्क प्रक्रियाएं और व्यापार सुविधा (एससी-सीपीटीएफ)
- राष्ट्रीय उपचार और बाजार पहुंच (एससी-एनटीएमए)
- उत्पत्ति के नियम (SC-ROO)
- संयुक्त समिति ने उप-समितियों को लंबित वार्ताओं को सहमत समय-सीमा के भीतर पूरा करने का निर्देश दिया है।

- बैठक की सह-अध्यक्षता नितिन कुमार यादव (भारत) और मस्तुरा अहमद मुस्तफा (मलेशिया) ने की, जिसमें सभी 10 आसियान सदस्य देशों ने भाग लिया।

AITIGA क्या है?

- आसियान-भारत वस्तु व्यापार समझौता (एआईटीआईजीए) भारत और 10 आसियान सदस्य देशों के बीच एक मुक्त व्यापार समझौता (एफटीए) है। इसका उद्देश्य वस्तुओं पर टैरिफ को कम करना या समाप्त करना, व्यापार को सुविधाजनक बनाना और आर्थिक सहयोग को मजबूत करना है।

AITIGA के बारे में

- हस्ताक्षरित: 13 अगस्त 2009
- लागू हुआ: 1 जनवरी 2010
- भाग: आसियान-भारत मुक्त व्यापार क्षेत्र (एआईएफटीए)
- भारत और आसियान के सदस् य देशों के बीच वस् तु व् यापार को कवर करता है।
- चल रही समीक्षा समझौते को अधिक आधुनिक, पारदर्शी और व्यवसाय के अनुकूल बनाने का प्रयास करती है।

समीक्षा क्यों महत्वपूर्ण है?

- व्यापार बाधाओं को दूर करने और सीमा शुल्क प्रक्रियाओं को सरल बनाने के लिए।
- भारतीय निर्यातकों के लिए बाजार पहुंच में सुधार करना।
- वर्तमान वैश्विक व्यापार प्रथाओं के अनुरूप व्यापार नियमों को अद्यतन करने के लिए।
- भारत और आसियान के बीच आपूर्ति श्रृंखलाओं और आर्थिक एकीकरण को मजबूत करना।
- द्विपक्षीय व्यापार और निवेश को बढ़ाना।

महत्व

- दक्षिण पूर्व एशिया के साथ भारत के आर्थिक संबंधों को मजबूत करता है।
- भारत की एक्ट ईस्ट नीति का समर्थन करता है।
- आसियान देशों के साथ आसान और तेज व्यापार को बढ़ावा देता है।
- क्षेत्रीय आपूर्ति श्रृंखला लचीलापन और आर्थिक सहयोग को बढ़ाता है।
- निर्यातकों, निर्माताओं और निवेशकों के लिए नए अवसर पैदा करने में मदद करता है।

परीक्षा फोकस पॉइंट

- समझौता: आसियान-भारत माल व्यापार समझौता (एआईटीआईजीए)
- प्रकार: मुक्त व्यापार समझौता (एफटीए)
- वर्तमान बैठक: 13वीं एआईटीआईजीए संयुक्त समिति की बैठक
- उद्देश्य: AITIGA की समीक्षा और आधुनिकीकरण करें
- हस्ताक्षरित: 13 अगस्त 2009
- से प्रभावी: 1 जनवरी 2010
- संबंधित ढांचा: आसियान-भारत मुक्त व्यापार क्षेत्र (एआईएफटीए)
- सह-अध्यक्ष (भारत): नितिन कुमार यादव, अतिरिक्त सचिव, वाणिज्य विभाग
- सह-अध्यक्ष (मलेशिया): मस्तुरा अहमद मुस्तफा, उप महासचिव (व्यापार)
- आसियान सदस्य: 10 देश
- संबंधित नीति: एक्ट ईस्ट पॉलिसी

नेपाल के पुनर्स्थापित जेष्ठ वर्ण महाविहार ने यूनेस्को विरासत संरक्षण पुरस्कार जीता

यह खबरों में क्यों है?

- नेपाल के ललितपुर में 17वीं सदी के बौद्ध मठ जेष्ठ वर्ण महाविहार को सांस्कृतिक विरासत संरक्षण के लिए 2025 यूनेस्को एशिया-पैसिफिक अवार्ड ऑफ मेरिट मिला है। 2015 के नेपाल भूकंप में गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त होने के बाद मठ को भारत सरकार से वित्तीय सहायता से बहाल किया गया था।

मुख्य बिंदु

- नेपाल के ललितपुर में जेष्ठ वर्ण महाविहार को सांस्कृतिक विरासत संरक्षण के लिए 2025 यूनेस्को एशिया-पैसिफिक अवार्ड ऑफ मेरिट से सम्मानित किया गया है।

- 2015 के गोरखा (नेपाल) भूकंप के दौरान मठ को व्यापक क्षति हुई और लगभग 13.78 करोड़ रुपये की भारतीय अनुदान सहायता के साथ बहाल किया गया।
- नेपाल में भारत के भूकंप के बाद पुनर्निर्माण कार्यक्रम के तहत बहाली परियोजना को अंजाम दिया गया था।
- इस परियोजना को पारंपरिक नेवारी वास्तुकला और लकड़ी की नक्काशी के संरक्षण के साथ आधुनिक भूकंप प्रतिरोधी तकनीक के सफलतापूर्वक संयोजन के लिए अंतरराष्ट्रीय मान्यता मिली।
- नेपाल सरकार और स्थानीय समुदाय के सहयोग से इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चरल हेरिटेज (INTACH) के तकनीकी सहयोग से यह जीर्णोद्धार पूरा किया गया।
- यह पुरस्कार भारत और नेपाल के बीच मजबूत सांस्कृतिक और विकास साझेदारी पर प्रकाश डालता है।

जेष्ठ वर्ण महाविहार के बारे में

- यह 17वीं सदी का बौद्ध मठ है जो नेपाल के ललितपुर (पाटन) में स्थित है।
- यह नेपाल के नेवारी बौद्ध वास्तुकला के महत्वपूर्ण उदाहरणों में से एक है।
- मठ स्थानीय समुदाय के लिए पूजा स्थल और एक जीवित सांस्कृतिक विरासत स्थल दोनों के रूप में कार्य करता है।

सांस्कृतिक विरासत संरक्षण के लिए यूनेस्को एशिया-प्रशांत पुरस्कारों के बारे में

- सांस्कृतिक विरासत संरक्षण के लिए यूनेस्को एशिया-प्रशांत पुरस्कार एशिया-प्रशांत क्षेत्र में विरासत भवनों और सांस्कृतिक स्थलों के संरक्षण और पुनर्स्थापना के उत्कृष्ट प्रयासों को मान्यता देता है। पुरस्कार उन परियोजनाओं को प्रोत्साहित करते हैं जो ऐतिहासिक प्रामाणिकता को संरक्षित करते हैं और यह सुनिश्चित करते हैं कि विरासत स्थल स्थानीय समुदायों के लिए उपयोगी बने रहें।

महत्व

- भूकंप के बाद नेपाल के पुनर्निर्माण में भारत के योगदान को मान्यता दी।
- भारत-नेपाल सांस्कृतिक और ऐतिहासिक संबंधों को मजबूत करता है।
- दक्षिण एशिया की साझा सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण को बढ़ावा देता है।
- यह दर्शाता है कि टिकाऊ विरासत संरक्षण के लिए आधुनिक इंजीनियरिंग को पारंपरिक वास्तुकला के साथ कैसे जोड़ा जा सकता है।
- सांस्कृतिक स्मारकों के संरक्षण में सामुदायिक भागीदारी को प्रोत्साहित करता है।

परीक्षा फोकस पॉइंट

• पुरस्कार: सांस्कृतिक विरासत संरक्षण के लिए यूनेस्को एशिया-प्रशांत मेरिट पुरस्कार (2025)
• पुरस्कृत स्थल: जेष्ठ वर्ण महाविहार
• स्थान: ललितपुर (पाटन), नेपाल
• स्थल का प्रकार: 17वीं सदी का बौद्ध मठ
• के साथ बहाल: भारत सरकार अनुदान सहायता
• बहाली लागत: एनपीआर 13.78 करोड़
• तकनीकी भागीदार: इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चरल हेरिटेज (INTACH)
• मान्यता देने वाले संगठन: यूनेस्को
• महत्व: भारत-नेपाल सांस्कृतिक और विकास साझेदारी को मजबूत किया।

स्वीडन वैश्विक पासपोर्ट सूचकांक 2026 में सबसे ऊपर है; भारत 125वें स्थान पर

यह खबरों में क्यों है?

- ग्लोबल पासपोर्ट इंडेक्स 2026 जारी कर दिया गया है, जिसमें स्वीडन ने दुनिया के सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट के रूप में पहला स्थान हासिल किया है। भारत 125वें स्थान पर खिसक गया है, जो भारतीय पासपोर्ट धारकों के लिए उपलब्ध अपेक्षाकृत सीमित वैश्विक यात्रा पहुंच को उजागर करता है।

मुख्य बिंदु

- स्वीडन ग्लोबल पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में शीर्ष पर है, जो दुनिया का सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट बन गया है।
- सूचकांक यात्रियों को प्रदान की जाने वाली वीजा-मुक्त और वीजा-ऑन-अराइवल पहुंच के आधार पर पासपोर्ट को रैंक करता है।
- भारत 125वें स्थान पर है, जो कई अन्य देशों की तुलना में अपेक्षाकृत कम अंतरराष्ट्रीय यात्रा गतिशीलता को दर्शाता है।
- उच्च रैंकिंग वाले देश व्यापक वीजा-मुक्त समझौतों और मजबूत राजनयिक संबंधों के कारण आसान अंतरराष्ट्रीय यात्रा का आनंद लेते हैं।

- रैंकिंग वीजा-मुक्त पहुंच, वीजा-ऑन-अराइवल सुविधाओं, इलेक्ट्रॉनिक यात्रा प्राधिकरणों (ईटीए) और वैश्विक गतिशीलता जैसे कारकों से प्रभावित होती है।
- सूचकांक किसी देश के राजनयिक संबंधों, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और यात्रा स्वतंत्रता के संकेतक के रूप में कार्य करता है।

ग्लोबल पासपोर्ट इंडेक्स क्या है?

- ग्लोबल पासपोर्ट इंडेक्स एक वार्षिक रैंकिंग है जो विभिन्न देशों द्वारा जारी किए गए पासपोर्ट की ताकत की तुलना उन गंतव्यों की संख्या के आधार पर करती है जहां उनके नागरिक पहले से वीजा प्राप्त किए बिना पहुंच सकते हैं।
- पासपोर्ट जितना मजबूत होगा, उसके नागरिकों को यात्रा की स्वतंत्रता उतनी ही अधिक होगी।

उपयोग किए गए पैरामीटर:

- वीज़ा-मुक्त यात्रा
- वीज़ा-ऑन-अराइवल एक्सेस
- इलेक्ट्रॉनिक यात्रा प्राधिकरण (ईटीए)
- अंतर्राष्ट्रीय गतिशीलता में आसानी
- वैश्विक राजनयिक जुड़ाव

महत्व

- विभिन्न देशों के नागरिकों द्वारा प्राप्त वैश्विक गतिशीलता को मापता है।
- किसी देश के राजनयिक संबंधों और अंतर्राष्ट्रीय समझौतों की ताकत को दर्शाता है।
- यात्रियों, व्यवसायों और नीति निर्माताओं को अंतरराष्ट्रीय यात्रा पहुंच का आकलन करने में मदद करता है।
- पर्यटन, शिक्षा, रोजगार और व्यापार के लिए सीमा पार आवाजाही में आसानी का संकेत देता है।

शीर्ष 5 देश – वैश्विक पासपोर्ट सूचकांक 2026

श्रेणी	भूक्षेत्र	कुल स्कोर
1	स्वीडन	96.05
2	स्विट्ज़रलैंड	95.57
3	फ़िनलैंड	95.53
4	जर्मनी	95.20
5 (संयुक्त)	नीदरलैंड	95.11
5 (संयुक्त)	डेनमार्क	95.11

निचले 5 देश - वैश्विक पासपोर्ट सूचकांक 2026

श्रेणी	भूक्षेत्र	कुल स्कोर
193	सीरिया	25.22
194	यमन	24.94
195	दक्षिण सूडान	24.33
196	सोमालिया	23.57
197	अफ़गानिस्तान	23.10

- परीक्षा टिप: इस ग्लोबल पासपोर्ट इंडेक्स (ग्लोबल सिटीजन सॉल्यूशंस) को हेनले पासपोर्ट इंडेक्स या आर्टन कैपिटल पासपोर्ट इंडेक्स के साथ भ्रमित न करें। प्रत्येक एक अलग पद्धति का उपयोग करता है, इसलिए रैंकिंग और स्कोर अलग-अलग होते हैं।

परीक्षा फोकस पॉइंट

- रिपोर्ट: ग्लोबल पासपोर्ट इंडेक्स 2026
- शीर्ष क्रम का देश: स्वीडन
- भारत की रैंक: 125 वीं
- रैंकिंग का आधार: वीज़ा-मुक्त, वीज़ा-ऑन-अराइवल और इलेक्ट्रॉनिक ट्रैवल ऑथराइजेशन (ईटीए) एक्सेस
- उद्देश्य: पासपोर्ट की वैश्विक ताकत और यात्रा स्वतंत्रता को मापें
- संकेतक: अंतर्राष्ट्रीय गतिशीलता और राजनयिक संबंध
- सर्वश्रेष्ठ पासपोर्ट धारक: स्वीडन
- मुख्य अवधारणा: पासपोर्ट स्ट्रेंथ / ग्लोबल मोबिलिटी इंडेक्स
- विचार किए गए कारक: वीज़ा-मुक्त पहुंच, वीज़ा-ऑन-अराइवल, ईटीए, यात्रा स्वतंत्रता, अंतर्राष्ट्रीय समझौते

ब्रिक्स ने अवैध मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ लड़ाई को मजबूत करने के लिए गुवाहाटी घोषणा को अपनाया

यह खबरों में क्यों है?

- ब्रिक्स देशों ने गुवाहाटी, असम में आयोजित ब्रिक्स एंटी-ड्रग एजेंसियों के प्रमुखों की बैठक के दौरान गुवाहाटी घोषणा को अपनाया है। घोषणा का उद्देश्य अवैध मादक पदार्थों की तस्करी, सिंथेटिक ड्रग्स और अंतरराष्ट्रीय संगठित अपराध से निपटने के लिए ब्रिक्स देशों के बीच सहयोग को मजबूत करना है।

मुख्य बिंदु

- गुवाहाटी घोषणा को असम के गुवाहाटी में 6-7 जुलाई 2026 को आयोजित ब्रिक्स एंटी-ड्रग एजेंसियों के प्रमुखों की बैठक के समापन पर अपनाया गया था।
- ब्रिक्स देशों ने सीमा पार मादक पदार्थों की तस्करी से निपटने के लिए खुफिया जानकारी साझा करने, सर्वोत्तम प्रथाओं के आदान-प्रदान और परिचालन सहयोग को मजबूत करने पर सहमति व्यक्त की।
- घोषणा सिंथेटिक ड्रग्स और संगठित अपराध से निपटने के लिए डिजिटल प्रौद्योगिकियों, डेटा-संचालित पुलिसिंग और नवीन प्रवर्तन उपकरणों के उपयोग पर जोर देती है।
- सदस्य देशों ने राष्ट्रीय कानूनों और अंतर्राष्ट्रीय दायित्वों के अनुसार समन्वय में सुधार करने का संकल्प लिया।
- भारत ने नशीले पदार्थों पर ब्रिक्स वर्चुअल टास्क फोर्स के गठन का प्रस्ताव रखा है ताकि अंतरराष्ट्रीय ड्रग कार्टेल के खिलाफ तेजी से खुफिया जानकारी साझा करने और समन्वित कार्रवाई को सक्षम किया जा सके।
- भारत ने अपना 2026-2029 एंटी-ड्रग रोडमैप भी प्रस्तुत किया, जो नशीली दवाओं के नेटवर्क को खत्म करने, जागरूकता अभियानों के माध्यम से नशीली दवाओं के दुरुपयोग को रोकने और उपचार और पुनर्वास सुविधाओं को मजबूत करने पर केंद्रित है।

गुवाहाटी घोषणा क्या है?

- गुवाहाटी घोषणा ब्रिक्स देशों द्वारा खुफिया साझाकरण, प्रौद्योगिकी-संचालित प्रवर्तन, क्षमता निर्माण और समन्वित नीतिगत कार्रवाई के माध्यम से अवैध नशीली दवाओं की तस्करी और अंतरराष्ट्रीय संगठित अपराध के खिलाफ सहयोग बढ़ाने के लिए अपनाई गई एक संयुक्त प्रतिबद्धता है।

महत्व

- नशीले पदार्थों की तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को मजबूत करता है।
- ब्रिक् स देशों के बीच खुफिया जानकारी के आदान-प्रदान में सुधार।
- नशीले पदार्थों के नियंत्रण में प्रौद्योगिकी और डिजिटल उपकरणों के उपयोग को बढ़ावा देता है।
- सिंथेटिक ड्रग्स और संगठित आपराधिक नेटवर्क के खिलाफ समन्वित कार्रवाई का समर्थन करता है।
- ब्रिक्स अध्यक्षता 2026 के तहत भारत के नेतृत्व को मजबूत करता है।

ब्रिक्स के बारे में

- ब्रिक्स प्रमुख उभरती अर्थव्यवस्थाओं का एक समूह है जो व्यापार, निवेश, वित्त, सतत विकास, प्रौद्योगिकी और वैश्विक शासन में सहयोग को बढ़ावा देता है।

इतिहास

• 2001 : ब्रिक शब्द गोल्डमैन सैक्स के जिम ओ'नील द्वारा गढ़ा गया था।
• 2006 : ब्रिक के विदेश मंत्रियों की पहली बैठक।
• 2009 : पहला ब्रिक शिखर सम्मेलन रूस के येकातेरिनबर्ग में आयोजित किया गया।
• 2010: दक्षिण अफ्रीका शामिल हो गया और ब्रिक्स ब्रिक्स बन गया।
• 2024: मिस्र, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरब और यूएई शामिल हुए।
• 2026: इंडोनेशिया 11वां सदस्य बना।

वर्तमान सदस्य (11)

- ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका, मिस्र, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात (यूएई), और इंडोनेशिया।

प्रमुख संस्थान

- न्यू डेवलपमेंट बैंक (NDB): 2014 में स्थापित; मुख्यालय – शंघाई, चीन।
- आकस्मिक रिजर्व व्यवस्था (सीआरए): सदस्य देशों के लिए 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर का वित्तीय सुरक्षा तंत्र।

परीक्षा फोकस पॉइंट

• घोषणा: गुवाहाटी घोषणा
• द्वारा अपनाया गया: ब्रिक्स राष्ट्र
• बैठक: नशीली दवाओं रोधी एजेंसियों के ब्रिक्स प्रमुखों की बैठक
• स्थान: गुवाहाटी, असम, भारत
• मेजबान देश: भारत
• द्वारा आयोजित: नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB), गृह मंत्रालय
• उद्देश्य: अवैध नशीली दवाओं की तस्करी और अंतरराष्ट्रीय संगठित अपराध के खिलाफ सहयोग को मजबूत करना
• प्रमुख फोकस क्षेत्र: खुफिया साझाकरण, सिंथेटिक ड्रग्स, डिजिटल प्रवर्तन, क्षमता निर्माण, परिचालन सहयोग

- भारतीय पहल: नारकोटिक्स पर ब्रिक्स वर्चुअल टास्क फोर्स का प्रस्ताव
- संबंधित समूह: ब्रिक्स (ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका, मिस्र, इथियोपिया, ईरान, इंडोनेशिया, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात)

दिल्ली सरकार ने सरकारी स्कूलों के आधुनिकीकरण के लिए मिशन कायाकल्प शुरू किया

यह खबरों में क्यों है?

- दिल्ली सरकार ने मिशन कायाकल्प शुरू किया है, जो बुनियादी ढांचे के उन्नयन और सामुदायिक भागीदारी के माध्यम से सरकारी स्कूलों को सुरक्षित, स्वच्छ, आधुनिक और छात्र-अनुकूल शिक्षण स्थानों में बदलने के लिए एक प्रमुख पहल है।

मुख्य बिंदु

- मिशन कायाकल्प का उद्देश्य दिल्ली भर में सरकारी स्कूलों के समग्र बुनियादी ढांचे में सुधार करना है।
- यह पहल कक्षाओं के नवीनीकरण, स्कूल भवनों की मरम्मत, प्रयोगशालाओं के उन्नयन, शौचालयों में सुधार, स्वच्छ पेयजल सुनिश्चित करने और परिसरों के सौंदर्यीकरण पर केंद्रित है।
- यह कार्यक्रम जिला प्रशासन, शिक्षा विभाग, सीएसआर संगठनों, गैर सरकारी संगठनों, बाजार संघों और स्थानीय समुदायों के सहयोग से लागू किया जा रहा है।
- विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए पुनर्निर्मित संवेदी पार्कों सहित समावेशी सुविधाओं के निर्माण पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।
- इस पहल का उद्देश्य सरकारी स्कूलों को न केवल शिक्षा का केंद्र बनाना है, बल्कि सुरक्षित, प्रेरक और आधुनिक शिक्षण वातावरण भी बनाना है।

मिशन कायाकल्प क्या है?

- मिशन कायाकल्प दिल्ली सरकार की एक प्रमुख पहल है जिसका उद्देश्य भौतिक बुनियादी ढांचे, स्वच्छता, सुरक्षा, पहुंच और सीखने की सुविधाओं में सुधार करके सरकारी स्कूलों का आधुनिकीकरण करना है। यह सार्वजनिक शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए सामुदायिक भागीदारी को भी प्रोत्साहित करता है।

उद्देश्य

- सरकारी स्कूलों के बुनियादी ढांचे का आधुनिकीकरण करें।
- एक स्वच्छ, सुरक्षित और समावेशी सीखने का माहौल प्रदान करें।
- बेहतर सुविधाओं के माध्यम से शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करें।
- सरकारी स्कूलों में छात्रों की भागीदारी और जनता का विश्वास बढ़ाना।
- स्कूल के विकास में समुदाय और सीएसआर भागीदारी को प्रोत्साहित करना।

महत्व

- सार्वजनिक शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करता है।
- छात्रों के लिए सीखने का बेहतर माहौल बनाता है।
- सरकारी स्कूलों में बुनियादी ढांचे को मजबूत करना।
- विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देता है।
- सरकार और स्थानीय समुदायों के बीच सहयोग को प्रोत्साहित करता है।

परीक्षा फोकस पॉइंट

- योजना: मिशन कायाकल्प
- द्वारा लॉन्च किया गया: दिल्ली सरकार
- उद्देश्य: सरकारी स्कूलों का आधुनिकीकरण और बुनियादी ढांचे में सुधार
- कवरेज: दिल्ली भर के सरकारी स्कूल
- प्रमुख घटक: स्मार्ट कक्षाएं, मरम्मत की गई इमारतें, प्रयोगशालाएं, शौचालय, पेयजल, स्वच्छ और हरित परिसर
- कार्यान्वयन: जिला प्रशासन, सीएसआर संगठनों, गैर सरकारी संगठनों, बाजार संघों और स्थानीय समुदायों के समर्थन से शिक्षा विभाग
- फोकस: सुरक्षित, स्वच्छ, आधुनिक और समावेशी सीखने के स्थान
- विशेष पहल: विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए संवेदी पार्क और बेहतर सुविधाएं।

लेट्स रिवाइज

- किस वैश्विक वित्तीय संगठन ने दिलीप अस्बे को अपने पर्यवेक्षी बोर्ड में नियुक्त किया है? स्विफ्ट (सोसाइटी फॉर वर्ल्डवाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन)।
- स्विफ्ट का फुल फॉर्म क्या है? सोसाइटी फॉर वर्ल्डवाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन।
- स्विफ्ट की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? 1973.
- दुनिया भर में बैंकों की विशिष्ट पहचान करने के लिए स्विफ्ट द्वारा किस कोड का उपयोग किया जाता है? स्विफ्ट कोड या बैंक पहचानकर्ता कोड (बीआईसी)।
- किन तीन देशों ने तीसरे देशों में छोटे मॉड्यूलर रिएक्टरों (एसएमआर) की तैनाती को संयुक्त रूप से बढ़ावा देने के लिए एक त्रिपक्षीय सहयोग ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? दक्षिण कोरिया, संयुक्त राज्य अमेरिका और जापान।
- जुलाई 2026 में पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो (BPR&D) के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आलोक कुमार मित्तल (आईपीएस, 1993 बैच, हरियाणा कैडर)।
- दूरदराज के ग्रामीण क्षेत्रों में 140 से अधिक कम लागत वाले सस्पेंशन फुटब्रिज के निर्माण के लिए किसे "ब्रिज मैन ऑफ इंडिया" के रूप में जाना जाता था? गिरीश भारद्वाज।
- किस अफ्रीकी देश ने द्विपक्षीय रक्षा सहयोग का विस्तार करने के लिए जुलाई 2026 में नई दिल्ली में भारत के साथ दूसरी संयुक्त रक्षा सहयोग समिति (JDCC) की बैठक आयोजित की? रवांडा।
- किस देश की ओलंपिक समिति ने हाल ही में आईओसी द्वारा अपना निलंबन अस्थायी रूप से हटा दिया है? रूसी ओलंपिक समिति (आरओसी)।
- आईओसी के नवीनतम निर्णय के बाद ओलंपिक खेलों के किस संस्करण में रूसी एथलीटों की वापसी देखी जा सकती है? लॉस एंजिल्स, यूएसए में 2028 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक।
- 13 वीं एआईटीआईजीए संयुक्त समिति की बैठक कहाँ आयोजित की गई थी? यह बैठक नई दिल्ली, भारत में आयोजित की गई थी।
- AITIGA का क्या अर्थ है? आसियान-भारत वस्तु व्यापार समझौता।
- आसियान-भारत वस्तु व्यापार समझौते (एआईटीआईजीए) पर कब हस्ताक्षर किए गए थे? इस समझौते पर 13 अगस्त 2009 को हस्ताक्षर किए गए थे।

- किस मठ को सांस्कृतिक विरासत संरक्षण के लिए 2025 यूनेस्को एशिया-पैसिफिक अवार्ड ऑफ मेरिट मिला? नेपाल में जेष्ठ वर्ण महाविहार।
- जेष्ठ वर्ण महाविहार कहाँ स्थित है? यह ललितपुर (पाटन), नेपाल में स्थित है।
- कौन सा अंतर्राष्ट्रीय संगठन सांस्कृतिक विरासत संरक्षण के लिए एशिया-प्रशांत पुरस्कार प्रदान करता है? यूनेस्को (संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन)।
- जेष्ठ वर्ण महाविहार की बहाली के लिए किस देश ने वित्तीय सहायता प्रदान की? भारत ने वित्तीय सहायता प्रदान की।
- जेष्ठ वर्ण महाविहार की बहाली के लिए भारत ने लगभग कितनी अनुदान सहायता प्रदान की? करीब 13.78 करोड़ रुपये।
- किस भारतीय संगठन ने जेष्ठ वर्ण महाविहार की बहाली के लिए तकनीकी सहायता प्रदान की? इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चरल हेरिटेज (INTACH)।
- ग्लोबल पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में कौन सा देश सबसे ऊपर है? स्वीडन
- ग्लोबल पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में भारत की रैंक क्या है? 125 वां
- कौन सा संगठन ग्लोबल पासपोर्ट इंडेक्स प्रकाशित करता है? वैश्विक नागरिक समाधान।
- ग्लोबल पासपोर्ट इंडेक्स 2026 के अनुसार भारतीय पासपोर्ट धारक कितने गंतव्यों तक वीजा-मुक्त या वीजा-ऑन-अराइवल के साथ पहुंच सकते हैं? 26 गंतव्य।
- नशीली दवाओं रोधी एजेंसियों के ब्रिक्स प्रमुखों की बैठक 2026 कहाँ आयोजित की गई थी? गुवाहाटी, असम, भारत।
- ब्रिक्स एंटी-ड्रग एजेंसियों के प्रमुखों की बैठक 2026 के दौरान कौन सी घोषणा अपनाई गई? गुवाहाटी घोषणा।
- गुवाहाटी घोषणा का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? अवैध नशीली दवाओं की तस्करी, सिंथेटिक ड्रग्स और अंतरराष्ट्रीय संगठित अपराध के खिलाफ सहयोग को मजबूत करना।
- ब्रिक्स एंटी-ड्रग बैठक के दौरान भारत ने किस नई पहल का प्रस्ताव रखा? नारकोटिक्स पर ब्रिक्स वर्चुअल टास्क फोर्स।
- किस सरकार ने मिशन कायाकल्प शुरू किया है? दिल्ली सरकार।
- मिशन कायाकल्प का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? बुनियादी ढांचे, सुरक्षा, स्वच्छता और सीखने की सुविधाओं में सुधार करके सरकारी स्कूलों का आधुनिकीकरण करना।
- मिशन कायाकल्प किस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है? पढ़ाई।
- मिशन कायाकल्प के तहत किन संस्थानों को लाभ होगा? दिल्ली भर में सरकारी स्कूल।

The ACHIEVERS IAS ACADEMY

The ACHIEVERS IAS ACADEMY PATNA

Daily NEWS CHRONICLE

IMPORTANCE OF CURRENT AFFAIRS IN UPSC EXAMINATIONS

Current Affairs hold a crucial place in the preparation for the UPSC Civil Services Examination. A comprehensive understanding of recent national and international developments helps aspirants strengthen their General Studies foundation and develop a well-rounded perspective on important issues. Topics such as government policies, schemes, economy, international relations, science and technology, environment, defence, social justice, governance, reports, indices, appointments, awards, and major global events are highly relevant for both the Prelims and Mains examinations. Regular study of current affairs not only enhances factual knowledge but also improves analytical ability, critical thinking, answer-writing skills, and decision-making aptitude. Since UPSC questions often connect contemporary developments with static subjects, consistent preparation of current affairs enables aspirants to understand issues in depth and present balanced, informed, and relevant answers. It also plays an important role in Essay writing, Ethics, and the Personality Test, giving candidates a strong edge throughout the examination process.

CONTACT US

+91 8434931877 achievers_ias_patna PATLIPUTRA GOLAMBAR

ACHIEVERS IAS ACADEMY (UPSC/BPSC) achieversiaspatna@gmail.com

Achievers IAS Academy www.achieversiaspatna.co.in Achievers IAS Academy, PATNA